



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 21 जनवरी, 2023 ई० (माघ 1, 1944 शक संवत्) [संख्या 3

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	41-62	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	19-26	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	59-84	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	3-4	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	27-30	975
			स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

## आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

डॉ० अनिल कुमार,  
निदेशक,  
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,  
उ0प्र0, प्रयागराज।

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**

अनुभाग-1

निरस्तीकरण

17 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 आई0/I-225560/2022/65-1001(001)/1/2021-उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सुश्री रीत सुदंरम का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है :

अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि	अनुक्रमांक/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
सुश्री रीत सुदंरम 05-12-1991	481318/01	श्री मणि कांत झा	H. N.-31-J, House Name-Ramayana, First floor, Bank Colony, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, Pin-8334008	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2-सुश्री रीत सुदंरम का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति-पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्नक प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या आई0/81375/2021/65-1001(001)/1/2021, दिनांक 22 जुलाई, 2021 द्वारा सुश्री रीत सुदंरम का राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही सुश्री रीत सुदंरम को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3-उल्लेखनीय है कि सुश्री रीत सुदंरम का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के निर्गतोपरान्त उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के अधोलिखित पत्रों, दिनांक 11 जनवरी, 2022 एवं 06 जुलाई, 2022 में सुश्री रीत सुदंरम को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना चिकित्सा परीक्षण कराकर शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है :

क्र0 सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	आई0/81375/2021/65-1001(001)/1/2021	22-07-2021
2	आई0/131055/2022/65-1001(001)/1/2021	11-01-2022
3	आई0/649/2022/65-1001(001)/1/2021	06-07-2022

4-स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी कराये जाने संबंधी पत्र जारी होने के 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने और कुल 03 पत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी कराये जाने हेतु अनुरोध करने के बाद भी सुश्री रीत सुंदरम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि सुश्री रीत सुंदरम उक्त पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं।

5-अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी सुश्री रीत सुंदरम का कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28/5/80-क-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से सुश्री रीत सुंदरम का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। इस आदेश के निर्गतोपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त सुश्री रीत सुंदरम द्वारा उक्त के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आई0/225571/2022/65-1001(001)/2/2021-उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर श्री शारदानंद तिवारी का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है :

अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि	अनुक्रमांक/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थायी पता	चयनित पद का नाम
श्री शारदानंद तिवारी 16-08-1995	036153/02	श्री राम किशोर तिवारी	कविता कुंज, बृजलोक कालोनी, दशहरा बाग, जनपद-बाराबंकी, उ0प्र0, पिन-225001	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2-श्री शारदानंद तिवारी का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति-पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्नक प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या आई0/97688/2021/65-1001(001)/2/2021, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा श्री शारदानंद तिवारी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही श्री शारदानंद तिवारी को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3-उल्लेखनीय है कि श्री शारदानंद तिवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 के निर्गतोपरान्त उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के अधोलिखित-पत्रों दिनांक 11 जनवरी, 2022 एवं 26 जुलाई, 2022 (जिसमें से 01 पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2022 को तिवारी के परिवारीजन को तामील कराया गया) में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना चिकित्सा परीक्षण कराकर शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है :

क्र0 सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	आई0/97688/2021/65-1001(001)/2/2021	14-09-2021
2	आई0/131055/2022/65-1001(001)/2/2021	11-01-2022
3	आई0/194537/2022/65-1001(001)/2/2021	26-07-2022

4-स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने संबंधी पत्र जारी होने के 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने और कुल 02 पत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध करने (जिसमें से 01 पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2022 को श्री तिवारी के परिवारीजन को तामील कराया गया) के बाद भी श्री तिवारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री शारदानंद तिवारी उक्त पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं।

5-अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी श्री शारदानंद तिवारी का कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28/5/80-क-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से श्री शारदानंद तिवारी का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। इस आदेश के निर्गतोपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री शारदानंद तिवारी द्वारा उक्त के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

आज्ञा से,  
हेमन्त राव,  
अपर मुख्य सचिव।

### सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

14 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 1425/सत्ताईस-1-2022-28/2022-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 सिविल संवर्ग के श्री अनिल कुमार, नवप्रोन्नत प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,  
अनीता वर्मा सिंह,  
विशेष सचिव।

नोशनल पदोन्नति

29 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 1521/सत्ताईस-1-2022-17/2021 टी0सी0-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 सिविल संवर्ग के श्री गिरीश चन्द्र अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 चयन वर्ष 2019-20 की एक आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति तथा कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 29 जून, 2022 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार द्विवेदी,  
अनु सचिव।

27 जुलाई, 2022, ई0

एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा Manual of Instructions for Railway Affecting Works (1987) को सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 30/98-27-सिं0-4-5-172/बाढ़/96, दिनांक 25 मार्च, 1998 द्वारा अंगीकृत किया गया।

आज्ञा से,  
अमित प्रणव,  
संयुक्त सचिव।

**NOTIFICATION***July 27, 2022*

It is hereby notified that the State of Uttar Pradesh has adopted Manual of Instructions for Railway Affecting Works (1987) vide its Letter No.-130/98-27-Irrigation-4-5-172/Flood/96, dated March 25, 1998.

By order,  
AMIT PRANAV,  
Joint Secretary.

अनुभाग-10

पदोन्नति

17 अगस्त, 2022 ई०

सं० 66/2022/1203/सत्ताईस-10-22-100(1)/22-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2022-23 में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) की घटित/प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (पे मैट्रिक्स लेवल-11, ग्रेड पे रु० 6,600) पर नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1	1694-ए	सत्य कुमार
2	1695-ए	अमित कुमार सिंह
3	1696-ए	विकास अग्रवाल
4	1697-ए	विजय कुमार वर्मा
5	1699-ए	गौरव श्रीवास्तव
6	1700-ए	सुनील चौधरी
7	1701	राकेश श्रीवास्तव
8	1702	राधेमोहन यादव
9	1702-ए	अखिलेश कुमार सिंह
10	1703	राकेश कुमार गुप्ता
11	1704	अरुण कुमार द्विवेदी
12	1704-ए	निशान्त सहाय
13	1705	हरीश कुमार तिवारी
14	1705-ए	राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी
15	1706	सुनील कुमार शुक्ला
16	1706-ए	अनुराग कुमार
17	1707	अनिल कुमार
18	1707-ए	नीरज कुमार गुप्ता

1	2	3
		सर्वश्री—
19	1708-ए	नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
20	1708-सी	प्रशान्त सिंह
21	1709-ए	हिमांशु विक्रम सिंह
22	1710-ए	अलका यादव
23	1711	शिवाकान्त
24	1711-ए	संजय कुमार
25	1712	निर्मल कुमार भारद्वाज
26	1712-ए	पंकज कुमार सिसौदिया
27	1713-ए	मनोज कुमार गौड़
28	1714-ए	शशांक कुमार
29	1715-ए	विनोद थापा
30	1716-ए	संजय कुमार सिंह
31	1717	भारत भूषण शर्मा
32	1717-ए	गौरव कुमार चतुर्वेदी
33	1718-सी	रतनेश गिरी
34	1719	राजेश कुमार मल्ल
35	1719-ए	राहुल अग्रहरि
36	1720	सुभाष चन्द्र
37	1720-ए	राजेश यादव
38	1722-ए	विकास दिवाकर
39	1723	अनिल कुमार सेंगर
40	1723-ए	रवि सागर
41	1724	गोविन्द नारायण शुक्ला
42	1724-ए	मंगल दास
43	1725-ए	पुनीत चौधरी
44	1726-ए	प्रमोद कुमार गौतम
45	1727-ए	केहर सिंह राना
46	1728	कमल कुमार तिवारी
47	1728-ए	सूर्य प्रकाश
48	1729	उमेश चन्द्र गुप्ता
49	1729-ए	रवेन्द्र प्रताप सिंह
50	1730	उपेन्द्र नाथ पाण्डेय

1	2	3
		सर्वश्री—
51	1732	अनिल कुमार सिंह
52	1735	देवेन्द्र सिंह
53	1736	अरुण कुमार
54	1739	सै० एजाजुल हुदा
55	1740	अविनाश कुमार
56	1742	राम कृष्ण मिश्र
57	1743	श्रवण कुमार सिंह
58	1744	सतेन्द्र प्रताप सिंह
59	1745	रसिक बिहारी गुप्ता
60	1749	सुधीर शर्मा
61	1750	सरोज कुमार चौरसिया
62	1758	कृष्ण चन्द्र
63	1759	संजीव कुमार गुप्ता
64	1760	राजेन्द्र कुमार शर्मा
65	1761	धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल
66	1762	धनेश चन्द्र राय
67	1763	अशोक कुमार पाण्डेय
68	1766	विद्यासागर तिवारी

2—उक्त अभियन्तागण की पदस्थापना के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
राम नारायण त्रिपाठी,  
संयुक्त सचिव।

अनुभाग—1  
पदोन्नति

22 अगस्त, 2022 ई०

सं० 1322/सत्ताईस-1-2022-28/2022—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० सिविल संवर्ग के श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 को प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2—उक्त पदोन्नति का आदेश विभिन्न न्यायालयों/मा० अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—श्री अनिल कुमार की तैनाती सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार द्विवेदी,  
अनु सचिव।



अनुभाग-13  
कार्यालय ज्ञाप  
10 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 708/सत्ताईस-13-2022—श्री रामसेवक द्वारा सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 01 नवम्बर, 1982 को कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री रामसेवक अवर अभियन्ता की तदर्थ सहायक अभियन्ता के पद पर शासन के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1989 द्वारा प्रोन्नति की गयी, जिसके क्रम में दिनांक 15 जुलाई, 1993 को तदर्थ सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। निर्देश याचिका संख्या 438(एफ)/आई0वी0/1989 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1995 के समादर में शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 1996 द्वारा श्री रामसेवक को दिनांक 14 अगस्त, 1989 से तदर्थ रूप से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किये जाने के संशोधित आदेश किये गये। उक्त से यह स्पष्ट है कि श्री रामसेवक द्वारा तदर्थ सहायक अभियन्ता के पद पर वास्तविक रूप से दिनांक 15 जुलाई, 1993 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 14 अगस्त, 1989 से दिनांक 15 जुलाई, 1993 के बीच की अवधि में यह अवर अभियन्ता के पद पर ही कार्यरत रहे।

2—इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा श्री रामसेवक का चयन वर्ष 1988-89 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित किये जाने के संस्तुति पर दिनांक 01 सितम्बर, 1997 द्वारा की गयी जिसके क्रम में दिनांक 22 सितम्बर, 1997 द्वारा अन्य सहायक अभियन्ताओं के साथ-साथ श्री रामसेवक को भी सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित किया गया।

3—सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग—8 के शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 1992 में यह प्राविधान है कि “ऐसे सहायक अभियन्ता जो नियमित हो, को 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवापूर्ण होने पर रु0 3,000-4,500 का वेतनमान दे दिया जाये। “उक्त व्यवस्था के अनुसार श्री रामसेवक की नियमित होने की तिथि 22 सितम्बर, 1997 से पूर्व दिनांक 14 अगस्त, 1994 से इन्हें यह उच्चतर वेतनमान की देयता श्रेणी में नहीं हैं किन्तु मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1995 के अनुपालन में शासनादेश सं0 1123/04-27-सिं-2-189/82, दिनांक 12 मई, 2004 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग द्वारा श्री रामसेवक को 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 14 अगस्त, 1994 से वेतनमान रु0 3,000-4,500 प्रदान किया गया।

4—सिंचाई अनुभाग-8 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 1992 में यह भी प्राविधान है कि “ऐसे सहायक अभियन्ता, जो नियमित हों और 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवापूर्ण कर ली हो और प्रोन्नत नहीं हुये हों को रु0 3,700-5,000 का वेतनमान दे दिया जाये। “श्री रामसेवक द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 1992 के अनुसार दिनांक 14 अगस्त, 2007 से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के आधार पर वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में याची द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका संख्या 1522/1999 रामसेवक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त निर्देश याचिका में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या रिट 39/15-सत्ताईस-2-09-निया-2012, दिनांक 22 जुलाई, 2015 द्वारा श्री रामसेवक के सहायक अभियन्ता के पद पर वास्तविक योगदान की तिथि दिनांक 15 जुलाई, 1998 के अनुसार इन्हें दिनांक 14 अगस्त, 2007 तक 18 वर्ष सेवापूर्ण न होने के कारण वैयक्तिक वेतनमान दिये जाने की देयता न पाते हुये इनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 एवं दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया गया।

5—तदनुक्रम में याची द्वारा पुनः निर्देश याचिका संख्या 572/2012 रामसेवक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को आदेश पारित किया गया जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है :

“प्रस्तुत निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2015 निरस्त किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह याची को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के दिनांक 14 अगस्त, 1989 से सन्तोषजनक सेवा के आधार पर गणना करते हुये वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 14 अगस्त, 2007 को देय मानते नियमानुसार इस निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्रदान करें।”

6—उक्त आदेश के अनुपालन में पुनः सम्यक् परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि श्री रामसेवक को उनसे कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति के दिनांक 14 अगस्त, 1989 से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ

पदोन्नति प्रदान की गयी। इसके उपरान्त लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों पर आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 1997 तक की सेवाओं को 05 वर्ष मानते हुये दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को सहायक अभियन्ता के पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने एवं वर्तमान में याची के कार्यरत होने के कारण ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रु0 7,600 की देयता बनती है। अतः तदनुसार शासन के कार्यालय आदेश सं0 920/सत्ताइस-13-2018-09निया/2012 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रु0 7,600 दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किये जाने संबंधी आदेश के क्रम में याची द्वारा योजित अवमानना याचिका संख्या 59/2018 रामसेवक बनाम श्री टी0 वेंकटेश तत्कालीन प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में अनुपालन आख्या भी दाखिल की गयी थी।

7—याची द्वारा प्रश्नगत अवमानना याचिका में पूरक शपथ-पत्र दाखिल कर मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के अनुपालन में दिनांक 14 अगस्त, 1989 से निरन्तर संतोषजनक सेवा के आधार पर गणना करते हुये वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 14 अगस्त, 2007 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

8—मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिनांक 18 फरवरी, 2021 को रिट याचिका संख्या 3824/2021, उ0प्र0 राज्य बनाम रामसेवक एवं अन्य योजित की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2021 को डिसमिस कर दिया गया। जिसके कारण मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2017 प्रभावी हो गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा पारित आदेश के प्रमुख अंश निम्नलिखित है :

In view of the above, once the earlier order passed by the Tribunal dated 18.09.1995 had attained finality, there was no justification for the petitioners to deprive the first respondent of the benefit of Personal Time Scale attached to the post of Assistant Engineer on completion of 18 years of service counted from 14.08.1989. The impugned order dated 07.11.2017 passed by the Tribunal therefore suffers from no legal infirmity. The petition is dismissed.

9—मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15 मार्च, 2021 से श्री रामसेवक, सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 14 अगस्त, 1989 से मानते हुये दिनांक 14 अगस्त, 2007 से 18 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु0 12,000-16,500 का लाभ देने के मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के क्रम में दिया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश इसलिये पारित किया गया है कि श्री रामसेवक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में यह अभिकथन दिया गया कि उनके कनिष्ठों श्री सहसरपाल एवं श्री दलजीत सिंह को उनकी ही स्थिति में दिनांक 14 अगस्त, 1989 से 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 14 अगस्त, 2007 से वेतनमान रु0 12,000-16,500 का लाभ दिया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा श्री रामसेवक के उक्त कथन का तत्समय प्रतिवाद नहीं किया जा सका।

10—मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15 मार्च, 2021 का जो आधार उल्लिखित किया गया है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत न करने के कारण हुआ है। परामर्शी विभाग (वित्त विभाग) के परामर्शानुसार यदि समान कनिष्ठों को गलत/नियम विरुद्ध लाभ दिया गया है तो उसे निरस्त कर इस तथ्य से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाना चाहिये था। इस प्रकार एक गलती के लिये दूसरी अन्य गलती नहीं की जा सकती है। यह मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धान्त है, उक्त की अनदेखी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य प्रकट न किये जाने के कारण हुई है। प्रकरण में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन एवं परामर्शी विभागों के परामर्शोपरान्त प्रकरण में रिव्यू योजित करने एवं जिन भी प्रकरणों में समान स्थिति में गलत/नियम विरुद्ध लाभ दिये गये हैं, उनको निरस्त कर उनका निराकरण करते हुये वसूली/समायोजन किया जाना है। इस प्रकार के प्रकरणों का व्यापक प्रभाव सम्पूर्ण प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के प्रकरणों पर पड़ेगा जो राजकोष पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

11—उपर्युक्त के संदर्भ में केवल प्रथम पद की नियुक्ति जब तदर्थ होती है तो उसी का विनियमितीकरण होता है। इसके बाद कोई तदर्थ पदोन्नति वेतन पाने के अलावा अन्य अर्थ नहीं रखती और जिस तिथि को नियमित पदोन्नति होती है उसी तिथि से सम्बन्धित सरकारी सेवक उस पर नियमित रूप से कार्यरत माना जाता है। चूंकि

श्री रामसेवक अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 01 नवम्बर, 1982 को तदर्थ रूप से नियुक्त हुये और दिनांक 14 अगस्त, 1989 से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गयी, जिसका आदेश दिनांक 15 जुलाई, 1993 को निर्गत हुआ एवं श्री रामसेवक का सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 22 सितम्बर, 1997 को नियमित नियुक्त हुये। अतः उन्हें सहायक अभियन्ता के धारित पद के संदर्भ में समयमान वेतनमान का कोई भी लाभ उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि दिनांक 22 सितम्बर, 1997 से ही देय होगा। उनकी सहायक अभियन्ता के पद के संदर्भ में तदर्थ सेवाओं के जोड़े जाने का कोई नियम विद्यमान नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विनियमितीकरण सदैव उस पद पर ही होता है जिस पद पर कोई सेवक सीधी भर्ती से तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया हो।

12-अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री रामसेवक का तत्कालीन सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ दोनों सहायक अभियन्ता श्री सहंसरपाल सिंह को दिनांक 18 अगस्त, 1989 से 18 अगस्त, 2007 से एवं श्री दलजीत सिंह, सहायक अभियन्ता को दिनांक 21 अगस्त, 1989 से 21 अगस्त, 2007 से 18 वर्ष की नियमित सेवा मानते हुये स्वीकृत किया गया उच्चतर वेतनमान अनियमित एवं नियम विरुद्ध हैं। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० जी-101/ई०-2, श्री रामसेवक, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के पश्चात् किसी भी सहायक अभियन्ता का उच्चतर वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः श्री रामसेवक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं के, अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्तानुसार सम्यक् विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री रामसेवक बनाम उ०प्र० राज्य में पुनर्विचार याचिका सं० 321/2022 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन श्री रामसेवक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ श्री सहंसरपाल सिंह एवं श्री दलजीत सिंह, सहायक अभियन्ता का उच्चतर वेतनमान निरस्त किया जाना सर्वथा उपयुक्त है।

13-ज्ञातव्य है कि श्री सहंसरपाल सिंह ने अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 09 मार्च, 1977 एवं श्री दलजीत सिंह ने अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 को सिंचाई विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। श्री सहंसरपाल सिंह का सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति दिनांक 18 अगस्त, 1989 को हुयी एवं श्री दलजीत सिंह की सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ पदोन्नति दिनांक 21 अगस्त, 1989 को हुयी। उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण दिनांक 22 सितम्बर, 1997 को किया गया। श्री सहंसरपाल सिंह एवं श्री दलजीत सिंह द्वारा क्रमशः दिनांक 18 अगस्त, 2007 एवं दिनांक 21 अगस्त, 2007 से 18 वर्ष की सेवा पर शासनादेश सं० 2656/10-27-सिं-2-9/91-2, दिनांक 08 नवम्बर, 2010 द्वारा वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 प्रदान किया गया। श्री सहंसरपाल सिंह एवं श्री दलजीत सिंह को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ के पत्र सं० 543/ई-3/ए०सी०पी०, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं पत्र सं० 720/ई-3/ए०सी०पी०, दिनांक 06 मई, 2016 के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वि०-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 2210/सत्ताईस-1-2016-66/10, दिनांक 15 जुलाई, 2016 से तृतीय ए०सी०पी० वेतन बैंड-4 वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700 प्रदान किया जा चुका है।

14-अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सक्षम स्तर/परामर्शी विभाग (वित्त/न्याय) के परामर्शानुसार श्री सहंसरपाल सिंह एवं श्री दलजीत सिंह को तदर्थ रूप से की गयी सेवाओं के आधार पर अनियमित/नियम विरुद्ध रूप से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान क्रमशः दिनांक 18 अगस्त, 2007 एवं दिनांक 21 अगस्त, 2007 से 18 वर्ष की सेवा पर दिये गये लाभ को कार्यालय ज्ञाप सं० 2656/10-27-सिं-2-9/91-2, दिनांक 08 नवम्बर, 2010 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पुनर्विचार याचिका सं० 321/2022 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

15-श्री सहंसरपाल सिंह एवं श्री दलजीत सिंह, सहायक अभियन्ताओं को त्रुटिवश/नियम विरुद्ध दिये गये उक्त लाभ की वसूली व समायोजन इत्यादि की कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन में प्रेषित करेंगे।

आज्ञा से,  
अनिल गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

## चिकित्सा विभाग

अनुभाग-8

नियुक्ति/तैनाती

20 जून, 2022 ई0

सं0 3फ/ए/तैनाती-प्रस्ताव-II/2018-19/2193-2202-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा वर्ष, 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से 565 चिकित्साधिकारियों की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध करायी गयी उक्त संस्तुतियों के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुजीत कुमार पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र, ग्राम डीहगंजारी, थाना जनसा, जनपद वाराणसी (चयन क्रमांक-एस-1880 एवं अनुक्रमांक-53100466259) तथा गृह जनपद को मौलिक रूप में अस्थाई रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये चिकित्सा इकाई पाली पी0एच0सी0, हरदोई में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वास्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] अभियोजन न चलाये जाने, मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[iii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iv] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[v] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[vi] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vii] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[viii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 4/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

(9) सम्बन्धित चिकित्सक यदि पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि यह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3-देश में कोरोना की गम्भीर महामारी के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1098/पांच-8-2020-जी0(290)/2017टी0सी0-II, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

आज्ञा से,  
रविन्द्र,  
सचिव।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

03 अगस्त, 2022 ई0

सं0 198117/2022/71-1001/478/2020-उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, पी0एम0आर0 विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 22 मई, 2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तें अनुमन्य होंगे।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3-अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5-अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

#### दिनांक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि० नं०	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहां तैनाती की गयी है
1	डा० गायकर रोहित रमेश पुत्र श्री गायकर रमेश केशव/53200023803	101 तनुजा सी०एच०एस० प्रेम नगर खरगांव कलवा, थाणे, महाराष्ट्र-400605	मेडिकल कालेज, बदायूं

सं० 198120/2022/71-1001/478/2020-उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, न्यूरोसर्जरी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 08 मई, 2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तें अनुमन्य होंगे।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3-अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5-अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

#### दिनांक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि० नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहां तैनाती की गयी है
1	डा० सुयश सिंह पुत्र श्री विनय कुमार सिंह/53200037338 अनारक्षित	19वीं ए०एन० झां मार्ग, जार्ज टाउन, प्रयागराज, उ०प्र०। पिन-211002	मेडिकल कालेज, झांसी

सं० 198122/2022/71-1001/478/2020-उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, रेडियोथेरेपी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तें अनुमन्य होंगे।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3-अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5-अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

#### दिनांक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि० नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहां तैनाती की गयी है
1	डा० सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री महावीर प्रसाद सैनी/53200021568/ अनारक्षित	नियर ओल्ड पोस्ट आफिस लक्ष्मणगढ़, जिला सिकर, राजस्थान, पिन-332311	मेडिकल कालेज, झांसी

सं० 198124/2022/71-1001/478/2020-उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, थोरेसिक सर्जरी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 08 मई, 2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में



उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों अनुमन्य होंगे।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3-अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5-अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

## दिनांक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/ पति का नाम/रजि० नं०	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहां तैनाती की गयी है
1	डा० स्वाति पाठक पत्नी डा० अभिनव कुमार श्रीवास्तव/53200018388	डी०-1 राजाजीपुरम, लखनऊ, उ०प्र०, पिन-226017	मेडिकल कालेज, आगरा

सं० 198128/2022/71-1001/478/2020-उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, स्कैन एण्ड वीडियो विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2020 एवं 08 मई, 2020 में की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल निम्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तें अनुमन्य होंगे।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन लम्बित न होने तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3-अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

5-अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

### दिनांक 03 अगस्त, 2022 का संलग्नक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/ पति का नाम/रजि० नं०/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहां तैनाती की गयी है
1	डा० श्वेता कुमार पत्नी श्री संतोष कुमार/53200030803/अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/महिला	99, न्यू इन्दिरा कालोनी, राजन नगला, भोलेपुर फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उ०प्र० पिन-209601	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
2	डा० रश्मि सिंह पत्नी डा० राकेश चन्द्र चौरसिया/53200000051/ अनारक्षित/सामान्य/महिला	सी-33/58-बी-2-के सनवीम स्कूल के पीछे सिगरा छित्तपुर, वाराणसी कैण्ट, उ०प्र०, पिन-221002	मेडिकल कालेज, बदायूं।
3	डा० राहुल बाल्मीकि पुत्र श्री कन्हय्य/53200005065/ अनु० जाति	594 घ/391 नीलमथा भगवन्तनगर, दिलकुशा, लखनऊ, उ०प्र०, पिन- 226002	मेडिकल कालेज, कन्नौज।

आज्ञा से,  
आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

### शुद्धि-पत्र

कार्यालय-ज्ञाप

07 जुलाई, 2022 ई०

सं० गोपन/को०के/2022/1320-31-शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 5-8099/43/2022-8-1/160660/2022-दिनांक 27 अप्रैल, 2022 द्वारा डा० तरुण राजपूत, चिकित्साधिकारी (वरि० क्र०-12411क-1) सामु० स्वा० केन्द्र, भूडबराल, जनपद मेरठ को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 2738/2011 डा० तरुण राजपूत बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03 जुलाई, 2015 के क्रम में दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 04 वर्षीय तृतीय विशिष्ट ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया गया था, जिसमें त्रुटिवश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थान पर मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ अंकित हो गया है।

इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या गोपन/कोर्टकेस/2022/1029, दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2-अतएव शासन के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 अप्रैल, 2022 में अंकित मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के स्थान पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पढ़ा/समझा जाये।

3-अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5-8099/43/2022-8-1/160660/2022, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,  
शिवगोपाल सिंह,  
संयुक्त सचिव।

अनुभाग-5  
नियुक्ति/तैनाती  
16 जून, 2022 ई0

सं0 31फ/दन्त/2022/721-32-उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्न सूची में अंकित 05 दन्त सर्जन वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 (लेवल-10) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित दन्त सर्जन को उ0प्र0 दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित दन्त सर्जन का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु दन्त सर्जन अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित दन्त सर्जन, जिनके सम्मुख औपबन्धिक अंकित है, निम्न प्रारूप पर चरित्र/प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित दन्त सर्जन को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनदेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित दन्त सर्जन-पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित दन्त सर्जन विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-8 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित दन्त सर्जन निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती स्थान पर योगदान दिये जाने की तिथि से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा 02 वर्ष की अवधि तक इनका क्रमशः अन्तरा-जनपदीय एवं अन्तर-जनपदीय स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इन 02 वर्षों के अन्तराल में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा ही इनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(8) सम्बन्धित दन्त सर्जन को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[2] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[3] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[6] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[7] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2-उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3-नियुक्ति/तैनाती से सम्बन्धित दन्त सर्जनों का विवरण निम्नवत् है :

क्र० सं०	दन्त सर्जन का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1	डा० स्वाती सिंह	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	प्रयागराज	ग्राम कोटवा, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज-22150	सामु० स्वा० केन्द्र, भूडबरा एट उपलैहड़ा, मेरठ।
2	डा० अम्बालिका विश्वास	श्री अरविन्दा कुमार विश्वास	दक्षिणी अण्डमान	निकट लक्ष्मी मोटर गैराज, गराचारमा-1, दक्षिणी अण्डमान-744105	सामु० स्वा० केन्द्र, मिश्रिख, सीतापुर।
3	डा० विशाल ब्रिहान	श्री देवेन्द्र सिंह	नई दिल्ली	आ०जेड० 12/7, रोशन गार्डन नजफगढ़, साउथ वेस्ट, दिल्ली नई दिल्ली	सामु० स्वा० केन्द्र, मवाना, मेरठ।
4	डा० वी०ई० संतोष कन्ना (औपबन्धिक)	श्री सी० इकम्बरम	वेल्लौर, तमिलनाडु	2बी०, चौथी गली, भवानीनगर, थरपतवेदु, कटपड़ी, वेल्लौर, तमिलनाडु-636007	सामु० स्वा० केन्द्र, हरिअवा, हरदोई।
5	डा० जियाउर रहमान	श्री मसीउर रहमान	पूर्णिया, बिहार	ग्राम नवाबगंज पोखरिया, पोस्ट-पूरनगंज, जनपद-पूर्णिया, बिहार-854317	सामु० स्वा० केन्द्र, टप्पल, अलीगढ़।

आज्ञा से,  
रविन्द्र,  
सचिव।

### खाद्य प्रसंस्करण विभाग

नियुक्ति/तैनाती

13 अक्टूबर, 2022 ई०

सं० 555(1)/58-2-2022-2/2022-खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप तथा आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मा० राज्यपाल महोदया श्री सुजीत कुमार राजभर, पुत्र श्री राधेश्याम राजभर, निवासी-मकान नं० 405, कुशवाहा बस्ती चन्दासी, मुगलसराय, जनपद चन्दौली, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-232101 (जन्मतिथि 05 जनवरी, 1995) को प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, श्रेणी-2, वेतनमान रु० 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर निम्न शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी के रिक्त पद पर नियुक्ति/तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करती है :

1-श्री सुजीत कुमार राजभर, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवानियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री सुजीत कुमार राजभर को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों, जो भी हो, देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ में योगदान अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

5—योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री सुजीत कुमार राजभर को योगदान करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करने होंगे :

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)

[2] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[3] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[4] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[5] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7— श्री सुजीत कुमार राजभर की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री सुजीत कुमार राजभर अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,  
मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २१ जनवरी, २०२३ ई० (माघ १, १९४४ शक संवत्)

### भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,  
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION]

### NOTIFICATION

January 17, 2023

**No. 11/VIIIc, Allahabad**—The Hon'ble Chief Justice and Hon'ble Judges of the High Court of Judicature at Allahabad in the Full Court meeting held on 11-01-2023, resolved that "the terms "district judiciary" and "trial Courts" shall be used instead of "subordinate judiciary" and "subordinate Courts", respectively, in reference to all Courts other than the High Court, in the State of Uttar Pradesh."

Therefore, all concerned are hereby informed, accordingly.

By order of the Court,  
ASHISH GARG,  
Registrar General.

### कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

०३ जनवरी, २०२३ ई०

सं० २०/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/२०२३—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, २००९ (अधिनियम संख्या-४ सन् २००९) की धारा-६ के उपधारा (१) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

## अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम,	सुजौली	सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-1	39
2	नानपारा, बहराइच	अल्पिका	सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-2	52
3			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-3	18
4			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-4	62
5			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-5	66
6			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-6	54
7			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-7	67
8			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-8	17
9			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-9	41
10			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-10	70
11			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-11	50
12			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-12	73
13			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-13	45
14			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-14	38
15			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-15	65
16			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-16	31
17			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-17	47
18			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-18	59
19			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-19	60
20			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-20	32
21			सुजौली अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-21	42

**टिप्पणी**—उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

## कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई0

सं० 20/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :



## अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	हरखापुर अल्पिका	हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-1	134
2			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-2	51
3			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-3	150
4			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-4	115
5			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-5	94
6			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-6	88
7			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-7	38
8			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-8	75
9			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-9	98
10			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-10	95
11			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-11	64
12			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-12	81
13			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-13	60
14			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-14	68
15			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-15	62
16			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-16	48
17			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-17	69
18			हरखापुर अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-18	55

**टिप्पणी**—उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

## कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई०

सं० 20/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

## अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5 हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	मधवापुर राजबहा	मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-1	65
2			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-2	64
3			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-3	32
4			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-4	28
5			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-5	89
6			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-6	94
7			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-7	170
8			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-8	112
9			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-9	90
10			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-10	89
11			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-11	78
12			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-12	147
13			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-13	44
14			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-14	45
15			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-15	50
16			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-16	42
17			मधवापुर राजबहा कुलाबा समिति संख्या-17	29

**टिप्पणी**—उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

## कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई०

सं० 20/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

**अनुसूची**

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम,	बोझिया	बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-1	59
2	नानपारा, बहराइच	अल्पिका	बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-2	92
3			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-3	18
4			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-4	52
5			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-5	37
6			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-6	93
7			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-7	34
8			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-8	54
9			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-9	76
10			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-10	48
11			बोझिया अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-11	70

**टिप्पणी**—उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

03 जनवरी, 2023 ई0

सं० 20/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

**अनुसूची**

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलाबा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम,	उर्ला अल्पिका	उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-1	51
2	नानपारा, बहराइच		उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-2	59
3			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-3	80
4			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-4	61
5			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-5	71
6			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-6	80
7			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-7	54
8			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-8	55
9			उर्ला अल्पिका कुलाबा समिति संख्या-9	25

**टिप्पणी**—उक्त कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

03 जनवरी, 2023 ई0

सं० 20/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

## अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	कुलावा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम,	भिउरा अल्पिका	भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-1	09
2	नानपारा, बहराइच		भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-2	54
3			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-3	15
4			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-4	38
5			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-5	15
6			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-6	94
7			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-7	15
8			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-8	55
9			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-9	13
10			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-10	13
11			भिउरा अल्पिका कुलावा समिति संख्या-11	55

**टिप्पणी**—उक्त कुलावा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
सक्षम नहर अधिकारी,  
एवं अवर अभियन्ता,  
सरयू नहर खण्ड-प्रथम,  
नानपारा, बहराइच।

## अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई०

सं० 21/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 के उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहों पर बनी राजबहा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

## अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	राजबहा समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	सरयू योजक नहर	मधवापुर राजबहा समिति	1327

**टिप्पणी**—उक्त राजबहा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
सक्षम नहर अधिकारी,  
एवं अधिशासी अभियन्ता,  
सरयू नहर खण्ड-प्रथम,  
नानपारा, बहराइच।

**अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0 22/स0न0ख0प्र0ना0/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

**अनुसूची**

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	सरयू योजक नहर	सुजौली अल्पिका समिति	1073

**टिप्पणी**—उक्त अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

**अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0 22/स0न0ख0प्र0ना0/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

**अनुसूची**

क्र सं0	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	सरयू योजक नहर	हरखापुर अल्पिका समिति	1445

**टिप्पणी**—उक्त अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

**अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0 22/स0न0ख0प्र0ना0/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

**अनुसूची**

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच	सरयू योजक नहर	बोझिया अल्पिका समिति	709

**टिप्पणी**—उक्त अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड—प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

### अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई०

सं० 22/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

#### अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड—प्रथम, नानपारा, बहराइच	मधवापुर राजबहा	उर्ला अल्पिका समिति	536

**टिप्पणी**—उक्त अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड—प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

### अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

03 जनवरी, 2023 ई०

सं० 22/स०न०ख०प्र०ना०/पिम/2023—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :

#### अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैत्रक नहर का नाम	अल्पिका समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टर
1	सरयू नहर खण्ड—प्रथम, नानपारा, बहराइच	सरयू योजक नहर	भिउरा अल्पिका समिति	376

**टिप्पणी**—उक्त अल्पिकाओं पर बनी अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड—प्रथम, नानपारा, जनपद बहराइच के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
सक्षम नहर अधिकारी,  
एवं सहायक अभियन्ता,  
सरयू नहर खण्ड—प्रथम,  
नानपारा, बहराइच।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 जनवरी, 2023 ई० (माघ 1, 1944 शक संवत्)

### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,  
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

### खण्ड-घ

### जिला पंचायत, हमीरपुर

24 दिसम्बर, 2022

### ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दुकान व अन्य व्यवसाय नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि

सं० 318/21-एल०बी०ए०/उपविधि-प्रकाशन-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत हमीरपुर ने जनपद हमीरपुर के ग्राम्य क्षेत्र में, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, सार्वजनिक सड़क एवं स्वयं की भूमि पर दुकान व अन्य व्यवसाय करने सम्बंधी कार्य करने को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 यथा संशोधित की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रचलित उपविधि सं०-5381-23-एल०बी०ए०-51 दिनांक 24 सितम्बर, 1991, उपविधि प्रकाशन 01 नवम्बर, 1997 के स्थान पर संशोधित उपविधि बनाई गई है। यह उपविधि उ०प्र० शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी

### परिभाषायें

- 1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
- 2-ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

### उपविधि

- 1-यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- 2-यह उपविधि दुकानें एवं अन्य व्यवसाय को विनियमित करने सम्बंधी उपविधि कहलायेगी।
- 3-कोई भी व्यक्ति/संस्था जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस व्यक्ति/संस्था ने जिला पंचायत, हमीरपुर में निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो।

4—प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू माह अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में रु0 100.00 तक निर्धारित लाइसेंस शुल्क में रु0 10.00 विलम्ब शुल्क तथा रु0 100.00 से रु0 500.00 तक निर्धारित लाइसेंस शुल्क में रु0 25.00 विलम्ब शुल्क तथा रु0 500.00 से अधिक लाइसेंस शुल्क पर रु0 50.00 विलम्ब शुल्क प्रति लाइसेंस शुल्क सहित जमा करना होगा।

5—उपविधि 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क से नये व्यवसायी मुक्त होंगे परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी की अनुमति से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6—उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की वसूली/उगाही सामान्यतः अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से कराई जायेगी, कर्मचारियों के अभाव में पंचायत हित में लाइसेंस शुल्क की वसूली की नीलामी ठेके पर देने की कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर में निहित होगा। वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी—

(अ) ठेका/नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी, नीलाम समिति में जिला पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होंगे।

7—ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उपविधि में निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था को इस आधार पर लाइसेंस शुल्क से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसने किसी अन्य संस्था, निकाय अथवा सम्बन्धित विभाग लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, प्रत्येक व्यवसायी को हर हालत में जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8—उपविधि के अधीन कोई भी लाइसेंस शुल्क का बकाया उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय-8 में वर्णित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

9—जिला पंचायत, हमीरपुर के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा पंचायत का कर्मचारी जिसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है किसी भी दुकान का निरीक्षण कर शुल्क जमा कराने का अधिकारी होगा साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कम दर्जे का न हो किसी भी उचित समय पर किसी भी दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थ या अन्य बिक्री योग्य सामग्री का निरीक्षण करते हैं, उन्हें अधिकार होगा कि ऐसे दुकान पर रखे गये खाद्य पदार्थ जो मनुष्यों के उपयोग हेतु उचित हो तत्काल नष्ट कर दें जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10—इस उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंसधारक द्वारा उपविधि के किसी भी धारा, उपधारा का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लाइसेंस को स्थगित कर दे अथवा निरस्त कर दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष जिला पंचायत हमीरपुर के समक्ष आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर की जा सकती है। इस विषय पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

11—जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा बनाई गयी उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस धारकों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा —

(क) कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो स्वयं ही उपविधि में वर्णित व्यवसाय कर सकता है और न ही किसी ऐसे रोगी व्यक्ति को व्यवसाय में नौकर या सहायक के रूप में सेवायोजित कर सकता है।

(ख) कोई भी लाइसेंसधारक/व्यक्ति खाद्य पदार्थ को बनाने या रखने हेतु धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेगा जो खाद्य पदार्थ को किसी भी प्रकार विकृत कर दूषित करते हो अथवा जिनमें बनाया हुआ अथवा रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।

(ग) खाद्य पदार्थ को बिक्री के लिये रखे गये साफ बर्तनों में इस प्रकार ढककर रखे जायेंगे जिनमें उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव-जन्तु बैठने न पाये जिससे खाद्य सामग्री हानिप्रद होने की सम्भावना न रहे।



(घ) प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने दुकान के सामने एक साइन बोर्ड लगवाना पड़ेगा जिसमें दुकान का नाम, व्यवसाय का विवरण, लाइसेंस धारक का नाम तथा रेट आदि भी अंकित करना होगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित व्यवसाय करने वाले लाइसेंस धारक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप बाटों का प्रयोग करना होगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के निर्देश का अनुपालन करना होगा।

12-उपविधि के प्रस्तर-6 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में लाइसेंस शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे-

(क) नीलाम/ठेका स्वीकृत के उपरान्त उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तों के अनुसार इकरार करना होगा।

(ख) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर "जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो" अनुबन्ध करना होगा।

(ग) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

(घ) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रहकर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित शर्तों के साथ पंचायतीराज उ0प्र0 शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

13-उपविधि में वर्णित दुकानें व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत है -

क्र0सं0	दुकान का प्रकार/व्यवसाय विवरण	लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (वस्त्र भण्डार)	300.00
2	कपड़ा की दुकान थोक	500.00
3	परचून की दुकान फुटकर (छोटी)	300.00
4	परचून की दुकान बड़ी (थोक)	500.00
5	किराना की फुटकर (छोटी)	300.00
6	किराना की बड़ी दुकान (थोक)	1,000.00
7	गल्ला खरीद बिक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आढ़त) (10 कु0 से अधिक पर)	1,000.00
8	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कु0 तक)	500.00
9	सोने चादी की आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	2,000.00
10	साने चांदी के आभूषण बनाने की दुकान	500.00
11	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवायें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अन्य (छोटी)	500.00
12	मेडिकल स्टोर (थोक) देशी दवायें, होम्योपैथिक अन्य	1,000.00

1	2	3
		रु0
13	विशात खाना	300.00
14	जनरल स्टोर	500.00
15	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	300.00
16	पुस्तक कापी (स्टेशनरी थोक)	500.00
17	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार)	500.00
18	चाय की दुकान (टी स्टाल)	300.00
19	पान की दुकान	300.00
20	चाय-पान की सम्मिलित दुकान	500.00
21	शर्बत, लस्सी, कोल्डड्रिंक, सोडावाटर आदि की दुकान	300.00
22	होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट	2,000.00
23	लोहे की बड़ी दुकान (जिसमें कटिया, मशीन, बाल्टी, सरिया, इंगल आदि शामिल)	1,000.00
24	लोहे की छोटी दुकान (जिसमें लाहे की बनी अन्य वस्तुयें शामिल)	500.00
25	साईकिल स्टोर (साईकिल एवं पुर्जों के विक्रेता थोक)	500.00
26	साईकिल स्टोर (साईकिल के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	200.00
27	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा, सिलवर आदि धातु बड़ी)	500.00
28	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, तांबा सिलवर अन्य धातु छोटी)	200.00
29	कपड़ा सिलाई (टेलरिंग शाप) जिसमें एक मशीन हो	200.00
30	कपड़ा सिलाई मशीन (टेलरिंग शाप) जिसमें एक से अधिक मशीन हो	500.00
31	जलाऊ लकड़ी की दुकान टाल	300.00
32	इमारती लकड़ी की दुकान जिसमें बल्ली लट्ठा आदि हो	500.00
33	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाले समान (फर्नीचर दुकान)	1,000.00
34	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500.00
35	बिल्डिंग मटेरियल (सप्लायर) अथवा किराये पर उठाने वाला	500.00
36	बूट हाउस जूता की दुकान शो रूम	500.00
37	जूता चप्पल की दुकान	300.00
38	जूता के अलावा चमड़े के बने हुए अन्य सामान की दुकान (लेदर स्टोर)	200.00
39	रैक्सीन तिरपाल आदि के बैग अटैची तथा अन्य सामान की दुकान	500.00
40	स्पंच के गद्दे तकिया सोफा प्लास्टिक फर्नीचर विक्रेता	1,000.00

1	2	3
		रु0
41	कृषि यंत्र (कृषि औजार)	300.00
42	बीज भंडार समस्त प्रकार के बीज भंडार (सरकारी बीज बाजार छोड़कर)	300.00
43	टीन चद्दर के बाक्स, पलंग, कुर्सी स्टील फर्नीचर दुकान	500.00
44	वाच शाप घड़ी विक्रेता (जेब, हाथ, अलार्म घड़ी)	500.00
45	वाच रिपेयर दुकान (समस्त प्रकार की घड़ी के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत)	200.00
46	बिजली के सामान की दुकान (समस्त विद्युत् उपकरण एवं मरम्मत)	500.00
47	रोड लाइट (बिजली सजावट साउण्ड सर्विस)	500.00
48	रसायनिक खाद दुकान (जिसमें सरकार खाद व गोदम न हो)	300.00
49	फलों की दुकान	300.00
50	सब्जी की दुकान	300.00
51	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	500.00
52	कांच व चीनी पत्थर के सामान की दुकान (काकरी दुकान)	200.00
53	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	200.00
54	बाल कटिंग (सैलून) दुकान	300.00
55	आटो पार्ट्स दुकान (दुपहिया वाहन)	500.00
56	आटो पार्ट्स दुकान (चार पहिया वाहन)	500.00
57	मोटर गैरिज (दुपहिया वाहन)	500.00
58	मोटर गैरिज (चार पहिया वाहन)	1,000.00
59	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर पंचर, हवा भरने की दुकान	300.00
60	पम्पसेट एवं पार्ट्स विक्रय दुकान	1,000.00
61	धर्मकाटा	1,000.00
62	पशु आहार विक्री दुकान	200.00
63	मुर्गी पालन उद्योग	1,000.00
64	डेयरी फार्म (दुग्ध उद्योग)	1,500.00
65	हथियार अग्नेयास्त्र की दुकान	2,000.00
66	अफीम गांजा, भांग, ताड़ी की दुकान	1,000.00
67	देशी शराब की दुकान	2,000.00
68	विदेशी शराब की दुकान	3,000.00

1	2	4
		रु0
69	फोटो स्टूडियो, फोटो कापी, कम्प्यूटर सर्विस	1,000.00
70	रेडिमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	500.00
71	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एव पार्टस विक्रेता	500.00
72	टाइप राइटर, सिलाई मशीन एव पार्टस मरम्मत कार्य	200.00
73	पी0सी0ओ0 (दूर संचार सेवा) मोबाइल दुकान	1,000.00
74	मशीन अथवा हाथ से जूता चप्पल निर्माण कर्ता	300.00
75	गुड़, लाई, चना, मूंगफली विक्रेता	200.00
76	गुड़, शक्कर, मैदा आदि की दुकान	200.00
77	लांझी (ड्राक्लीनर) दुकान	500.00
78	तम्बाकू विक्री की दुकान	500.00
79	रुई विक्रेता	500.00
80	सभी प्रकार खेल कूद स्पोर्ट्स दुकान	500.00
81	कबाड़ी की दुकान	300.00
82	सीमेन्ट, गिट्टी, पत्थर सीमेन्ट/प्लास्टिक पाइप (सिनेटरी), फिटिंग टायल्स मारबल की दुकान	2,000.00
83	रंग रोगन की दुकान (वार्निश पेंट) वाल पेंट, डिस्टैम्पर, इसनोसेम की दुकान	2,000.00
84	शामियाना, कुर्सी आदि किराये की दुकान (टेंट हाउस)	1,000.00
85	कोलतार (डामर) फिनायल विक्रेता	1,000.00
86	अण्डे की दुकान	300.00
87	घी, दूध, तेल की दुकान	200.00
88	हाथ ठेला फेरी अथवा खोन्चा (सिर पर) फेरी कार्य	100.00
89	लकड़ी के खिलौने बनाने व बिक्री की दुकान	300.00
90	दूध फेरी विक्रेता 10 ली0 तक	200.00
91	दूध फेरी विक्रेता 11 ली0 से 20 ली0 तक	200.00
92	दूध फेरी विक्रेता 21 ली0 से अधिक	550.00
93	खोवा उत्पादक फेरी द्वारा क्रय विक्रय	200.00
94	कपड़ों की रंगाई (रंगरेज)	200.00
95	सइन बोर्ड दीवाल पेंटिंग (पेन्टर) दुकान	200.00
96	कपड़ा/विशातखाना दुकान अन्य घरेलू सामान (फेरी द्वारा)	100.00
97	अन्य छोटे व्यवसाय	500.00

1	2	3
		रु0
98	आतिशबाजी की दुकान	1,000.00
99	नौटंकी कम्पनी खेल तमाशा व मनोरंजन शो आदि पर	1,000.00
100	बैण्ड बाजा	1,000.00
101	अन्य बाजा (बीन बाजार ढोल पंजाबी भांगड़ा)	500.00
102	रेडिया टी0वी0 इलेक्ट्रानिक समान की दुकान	500.00
103	रेडियों टी0वी0 अन्य इलेक्ट्रानिक समान के पुर्जे बिक्री व मरम्मत	500.00
104	फुटकर मिट्टी का तेल, कैरोसीन, डीजल, मोबिआयल	200.00
105	पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प	5,000.00
106	मिट्टी का तेल पम्प कोसीन	1,000.00
107	कोल्ड स्टोरेज	5,000.00
108	प्रापर्टी डीलर व्यवसाय	2,000.00
109	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स	500.00
110	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट वाहन सहित ट्रेवल्स	2,000.00
111	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट आटो रिक्शा (दो सीटर अथवा चार शीटर)	200.00
112	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स आटो रिक्शा (मेटाडोर) 7 सीट तक	500.00
113	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मिनी बस	700.00
114	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स बस	1,000.00
115	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स अन्य चार पहियों के व्यवसायिक वाहन	500.00
116	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स मोटर वाहन एजेंसी (सेल्स/सर्विस)	5,000.00
117	ट्रासपोर्ट एजेन्सी/ट्रासपोर्ट बिना वाहन के ट्रेवल्स स्कूलर/ मोटर साइकिल एजेंसी (सेल सर्विस)	5,000.00
118	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 बेड तक	1,000.00
119	स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नर्सिंग होम 20 से अधिक	2,000.00
120	ठंडी बियर की दुकान	2,000.00
121	बलू स्टाकिस्ट (डम्प) 2000 घन मी0 तक	1,000.00
122	बलू स्टाकिस्ट (डम्प) 2001 घन मी0 से अधिक	2,000.00
123	टायर रबडिंग की दुकान	1,000.00
124	अन्य बड़े व्यवसाय	5,000.00
125	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापित टावर्स आदि (टेलीफोन, मोबाइल टावर आदि)	10,000.00

14—उपविधि सं0-13 में वर्णित दुकानें तथा अन्य व्यवसायों को निर्धारित शुल्क में उसके प्रभावी तिथि से 3 वर्ष के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-2004(1)/33-2-2001-26 पी/2001, पंचायतीराज अनुभाग दिनांक 26 सितम्बर, 2002 में प्रदत्त दिये निर्देशानुसार दरों में नियमित शुल्क संशोधित किये जाने का अधिकार पंचायत में निहित है।

15—वाहनों के लाइसेंस न बनवाने वाले अथवा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जि0पं0 लिखित रूप से वाहन को अपनी अनुरक्षा में लेने का अधिकारी होगा और यदि एक सप्ताह निर्धारित किये गये शुल्क को अदा कर लाइसेंस प्राप्त न किया जायेगा तो बिना किसी के पकड़ा गया वाहन जि0पं0 अधिनियम के अन्तर्गत रिकवरी चालान कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण दायित्व वाहन स्वामी का होगा।

#### (द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

#### ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि

सं0 320/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गई शक्ति की प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई है। यह उपविधि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, तथा इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

#### उपविधि

1—यह उपविधि जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बंधी उपविधि कही जायेगी। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मिल/कारखाना/फैक्ट्री संचालित करने वाले व्यक्ति/संस्था को निम्न विवरण के अनुसार लाइसेंस शुल्क जिला पंचायत, हमीरपुर को देय होगा।

2—उपविधि में वर्णित मिल/कारखाना/फैक्ट्री के लिये व्यवसायवार निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। दरें निम्नवत् हैं—

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्तिचालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्तिचालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00

1	2	3
		रु0
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	8,000.00
28	स्टील, आयर्न आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयर्न आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल सब्जियों एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल सब्जियों एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लांट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्युमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना।	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना।	50,000.00
42	कृषि सम्बंधी यंत्र बनाने का कारखाना।	4,000.00
43	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना।	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना।	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना।	4,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना।	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना।	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00

1	2	3
		रु0
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना।	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना।	10,000.00
55	मचिस बनाने का कारखाना।	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना।	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना।	3,000.00
58	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना।	15,000.00
61	साफिट बनाने का कारखाना।	5,000.00
62	प्लाईबुड या सनमाइका बनाने का कारखाना।	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना।	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना।	3,000.00
65	लैमिनेशन का कारखाना।	5,000.00
66	दूध पैकिंग का कारखाना।	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना।	8,000.00
68	डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना।	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना।	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना।	8,000.00
71	बेल्लिंग राइस बनाने का कारखाना।	6,000.00
72	पीतल की राइस बनाने का कारखाना।	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना।	6,000.00
74	स्टील अलमारी, बक्शे मेज आदि बनाने का कारखाना।	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना।	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना।	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना।	7,000.00
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना।	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना।	2,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना।	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना।	3,000.00
82	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना।	7,000.00
83	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना।	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना।	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बंधी सामान बनाने का कारखाना।	10,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना।	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना।	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना।	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना।	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारखाना।	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना।	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना।	4,000.00



1	2	3
		रु०
94	बैट्री बनाने का कारखाना।	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना।	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना।	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना।	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना।	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना।	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना।	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना।	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना।	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00
110	विडियों सिलेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडीमेड गारमेन्ट का कारखाना।	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना।	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना।	15,000.00
118	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना।	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना।	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना।	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना।	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना।	25,000.00
123	जैविक कारखाना।	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

3—उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुये अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है।

क्र० सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु०
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (Small) (लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

4-प्रत्येक लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं मई में लाइसेंस शुल्क जमा करने पर बिलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। उसके पश्चात् लाइसेंस शुल्क जमा करने पर लाइसेंस शुल्क में 25 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ लाइसेंस शुल्क जमा किया जायेगा। नया लाइसेंस बनवाने पर लाइसेंसधारक बिलम्ब शुल्क से मुक्त होगा।

### (द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

24 दिसम्बर, 2022 ई0

### मोबाइल टावर एवं अन्य व्यवसायिक टावर स्थापना एवं नियंत्रण उपविधि

सं0 322/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत हमीरपुर ने जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न दूरसंचार एवं अन्य उद्देश्यों के लिये स्थापित टावरों, मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुरूप उपविधि बनायी है। जो अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

### उपविधि

**1-संक्षिप्त नाम**—(1) यह उपविधि जिला पंचायत मोबाइल टावर एवं अन्य व्यवसायिक टावर स्थापना एवं नियंत्रण उपविधिकही जायेगी।

(2) यह जिला पंचायत, हमीरपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

**2-परिभाषाये**—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

(1) “अधिनियम” से तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (यथा संशोधित) 1961 से है,

(2) “टावर” से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन, मोबाइल फोन, या अन्य फोन या अन्य दूर संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहककर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(3) “सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(4) “भवन” के अन्तर्गत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य किसी से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे चबूतरे मकानों की कुर्सियों, दरवाजे की सीढ़ियां दीवारें तथा हाते की दीवारें और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।

(5) “भूमि” भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा पानी से ढकी हो, भूमि में उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बांधी हुई वस्तुएं और भी अधिकार है जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हों।

(6) “जिला पंचायत से तात्पर्य जिला पंचायत, हमीरपुर से है।

(7) जिला पंचायत, हमीरपुर की सीमा से तात्पर्य—(नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्र से है।

(8) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हों।

**3—प्रतिशोध—**(1) अपर मुख्य अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी तरह की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) जिला पंचायत की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अपर मुख्य अधिकारी की लिखित एवं पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि और भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिस्थापित करेगा और न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उसके अधवासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

**4—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—**(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 100 (एक सौ) भुगतान करके जिला पंचायत, हमीरपुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिस्थापित किया जाना परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना एवं अभियंता, जिला पंचायत से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छल पर ऐन्टीना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियाँ अंकित की जायेंगी।

(8) एक ही टावर का उपयोग एक से अधिक फर्म, कम्पनी, सेवा प्रदाता, अभिकर्ता अनुज्ञापी या संविदाकर्ता आदि करती है तो प्रत्येक को अलग-अलग लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।

(9) ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेंस प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वाँछित होगी।

**5—अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें—**किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायगी

(1) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन जमा किया गया हो।

(2) टावर को समुचित स्थितियों एवं दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(4) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी. की समाप्ति एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(5) टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिस्थापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(6) लोकहित में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें।

(7) किसी भवन की छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(8) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिस्थापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो

(9) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्र में लगाने से बचा जाये किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(10) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मीटर से कम न हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा भौक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(11) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रान्समिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें सम्भव एक ही टावर परस्थापित कराना होगा।

(12) टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टीना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षणकर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(13) टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

#### (क) प्रतिबन्धित क्षेत्र—

(14) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(15) ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्टतया में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लागने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(16) जहाँ इससे ग्रामीण सुविधायें प्रभावित हों वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(17) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् की कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

(18) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति या उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(19) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(20) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**6—सम्पत्ति कर का आरोपण**—टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

**7—अनुज्ञा की अवधि एवं नवीनीकरण**—अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगी।

**8—टावर को हटाने की शक्ति**—यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिस्थापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो तो अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है—

(1) टावर हटाये जाने का व्यय ।

(2) ऐसी अवधि के दौरान टावर प्रतिस्थापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था. खड़ा किया गया था गाड़ा गया था के लिए हुई क्षति की धनराशि।

**9—टावर पर निर्वन्धन**—किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी।

(1) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(2) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं अन्य मार्गों की भूमि सीमा के भीतर।

(4) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(5) जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हों।

(6) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो

(7) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

**10—निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा**—जिला पंचायत, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

**11—अनुरक्षण**—(1) सभी टावर जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बो बांधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो ढांचागत और कलात्मक दोनों की दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं हैं, तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके कर्मचारी, अमिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से अच्छादित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

**12—प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**—अपर मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

**13—शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान की रीति**—(1) इस निमित्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा किया जायेगा जो जिला पंचायत सीमान्तर्गत ( नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका/नोटीफाइड एरिया को छोड़कर) न्यूनतम रु0 10,000.00 प्रति टावर प्रति एन्टीना प्रति वर्ष होगी। एक से अधिक एन्टीना में लाइसेंस शुल्क की दर रु0 3,000.00 प्रति एन्टीना अलग से होगी।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में देय होगा जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिस्थापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में बाहर कर दी जायेगी।

(4) यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत द्वारा जन सुविधायें या सी०सी०टी०वी० कैमरे, प्रकाश यन्त्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

### दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),

आयुक्त,

चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

## जिला पंचायत, चित्रकूट

24 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 328/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत चित्रकूट ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी है। यह उपविधि उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2-ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो, जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मस्ती, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-फ्लोर एरिया रेशियो (FAR-Floor Area Ratio) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground-Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय प्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधाएँ आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Land-scaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता-इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट से है।

22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत चित्रकूट से है।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य-अध्यक्ष, जिला पंचायत चित्रकूट से है।

24-बहु मंजिली भवन (Multy Storey Building) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कानर्स या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27-आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28-व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29-संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31-पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards के यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

### उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत चित्रकूट के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, गुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

### (क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1-उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(द) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(य) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(र) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ढा भरना।

### (ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2-प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।



(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(श) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3-बहु मंजिली भवन (Multi Storey Building) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी-

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

### (ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

अ-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब-प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स-प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

### (घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1-(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रेक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्राविधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground-Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है-

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मंचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मस्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिये।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिये ।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये ।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये ।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10: से कम न होना चाहिये ।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिये ।

4—(क) पार्क, टोट—लोट्स (Tot-Lots), परिदृश्य (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15: होगा !

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी ।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी ।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा ।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा ।

### (ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground-Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground-Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा ।

### (च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी ।

### (छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे—

क्र० सं०	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यवसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन (i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि (ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि (iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन सरकारी, अर्धसरकारी, कारपोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृ तिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेयरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए० टी० एम०	100	1.00	6	6

## (ज) सेट बेक (set-back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Land-scaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर		
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

## (झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथि गृह, हास्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

## (ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिंग

(i)--तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा--संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़े मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए !

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे-- स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वैट राईजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

## (ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम बोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 बोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305 m ) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305 m ) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

**(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना**

क—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी/भू-स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।

ख—जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे ।

ग—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए ।

घ—जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

ङ—सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी/भू-स्वामी का होगा ।

च—इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (Vibration) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

छ—अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

**(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें**

**क—आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन**

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 25 प्रति वर्ग मीटर होगी ।

**ख—व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन—**

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर होगी ।

**ग—(i) भूमि की प्लानिंग—**भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बाँटना ।

**(ii) भूमि विकास—**भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि ।

**(iii) भूमि का उपभोग—**भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे—निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी०पाईप आदि ।

**(iv) किसी परियोजना का (Ley out Plan) तलपट मानचित्र ।**

उपरोक्त ग—(i) से (iv) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

घ—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी ।

ङ—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी ।

च—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी ।

छ—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी । एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी ।

ज—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा

का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

झ-सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion-Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर व अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

ञ-सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10 रुपये प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5 रुपये प्रति मीटर होगी।

**नोट**—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

### (ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1-स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2-ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3-कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5-अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7-अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8-अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9-जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन-कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10-अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11-अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा करना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

**विवाद**—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बाध्यकारी होगा।

### (त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

### (थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर ले।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

### (द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत चित्रकूट यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

### कार्यालय, जिला पंचायत, चित्रकूट

उपविधि संशोधन

22 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 329/स्टोन क्रेशर-संशोधन उपविधि/जि0पं0चि0/2021-22-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश, संख्या 1152/33-2-2017-62जी/2018 पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के साथ प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुये स्टोन क्रेशर की प्रचलित/स्वीकृत उपविधि संख्या 08/LBA/उपविधि-जिला पंचायत चित्रकूट, 2005-06 जिला पंचायत चित्रकूट अपने ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत स्टोर क्रेशर (पत्थर गिट्टी तोड़ने की मशीन) की स्थापना एवं संचालन को नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि के मात्र प्रस्तर-17 में प्राप्त शासन के प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस शुल्क में आवश्यक संशोधन करने की उपविधि जो जिला पंचायत चित्रकूट के अन्य प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 28 अगस्त, 2021 द्वारा पारित है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित है। यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय में दे सकते हैं। निर्धारित अविधि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इलाहाबाद उ0 प्र0 गजट, दिसम्बर, 2005 ई0 (पौष-3,1027 शक् संम्वत्) 2005 द्वारा प्रकाशित उपविधि में 01 लगायत 20 धारायें उक्त तिथि से प्रभावी है, शासनादेश दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा उक्त उपविधि के प्रस्तर 17 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :

प्रचलित दरें	संशोधित दरें, (शासन के प्रस्ताव अनुसार )
धारा-17 अनुज्ञा-पत्र लाइसेंस रु0 मु0 3,000.00 (रु0 तीन हजार) प्रतिवर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिये देय होगा।	धारा-17 अनुज्ञा-पत्र लाइसेंस रु0 मु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) प्रतिवर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिये देय होगा।

ह0 (अस्पष्ट),  
आयुक्त,  
चित्रकूटधाम मण्डल,  
बांदा।





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 जनवरी, 2023 ई० (माघ 1, 1944 शक संवत्)

### भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

### भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2023 ई०  
पौष 13, 1944 (शक)

### अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-वि०प०/17/22/2023-बी०ई०-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में श्री ऋषि पाल सिंह के निर्वाचन को प्रश्नांकित करने वाली "2022 की निर्वाचन याचिका संख्या 17, श्री जसवंत सिंह बनाम श्री ऋषि पाल सिंह" में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के दिनांक 21 नवम्बर, 2022 के आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,  
सुमन कुमार दास,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 03<sup>rd</sup> January, 2023  
13<sup>th</sup> Pausha, 1944 (Saka).

### NOTIFICATION

No. 82/UP-LC/17/22/2023-BE-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the order dated 21.11.2022 of the High Court of Judicature at Allahabad in 'Election Petition No. 17 of 2022, Shri Jaswant Singh versus Shri Rishi Pal Singh', challenging the Election of Shri Rishi Pal Singh as Member of the Legislative Council of Uttar Pradesh from Aligarh Local Authorities' Constituency.

By order,  
SUMAN KUMAR DAS,  
Secretary,  
Election Commission of India.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****Case :-** Election Petition No. 17 of 2022**Petitioner :-** Jaswant Singh**Respondent :-** Rishi Pal Singh**Counsel for Petitioner :-** Jaswant Singh (In Person), Dinesh Kumar**Hon'ble Sanjay Kumar Singh, J.****Order on Civil Misc. Withdrawal Application.**

Pursuant to order of Hon'ble the Chief Justice dated 18.11.2022 this case has been taken up through Video Conferencing from Lucknow.

The petitioner-Jaswant Singh has filed this election petition for quashing the impugned order dated 23.03.2022 and to declare the election of the respondent as null and void. Thereafter, petitioner has filed aforesaid Civil Miscellaneous Withdrawal Application No. 2 dated 10.05.2022 mentioning therein that the petitioner does not want to press the election petition.

On the aforesaid application, notice was issued to the respondent vide order dated 22.07.2022 and direction for publication in official Gazette in view of Section 109 of the Representation of People Act, 1951 was also issued which has been complied with by the election petitioner.

Vide order dated 22.07.2022, publication has been made in the Government Gazette Uttar Pradesh on 13.08.2022, copy whereof has been filed by the election petitioner alongwith compliance affidavit dated 16.09.2022.

Vide order dated 17.10.2022, notice was issued to the respondent on his correct address on which office has submitted report dated 19.11.2022 which reads as under :-

"In compliance of Hon'ble Court's order dated 17.10.2022 the notice of withdrawal application was sent to the Respondent by registered Post with AD fixing 21.11.2022 for hearing as under :-

Rishi Pal Singh - Neither AD nor undelivered notice has been returned so far.

The online postal tracking report indicates that the delivery is confirmed, the same is place on record.

It is further submitted that learned counsel for the petitioner has filed the affidavit of service (03/22) annexing therewith the official gazette in which notice for withdrawal has been published.

*The Civil Misc. Withdrawal Application (no. 2/22) is put up for order."*

From the aforesaid tracking report, it is clear that the notice has been served upon the respondent but no one has put in appearance on his behalf.

In view of the above, the instant civil misc. withdrawal application is liable to be allowed.

Accordingly, the withdrawal application is allowed.

**Order on Election Petition.**

In view of the aforesaid, the Election Petition is dismissed as withdrawn.

**Order Date :-** 21.11.2022

Saurabh

(Sd.) SANJAY KUMAR SINGH, J.

By order,  
SUMAN KUMAR DAS,  
Secretary,  
Election Commission of India.

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।

पी०एस०यू०पी०-43 हिन्दी गजट-भाग 7-ख-2023 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
पी०एस०यू०पी०-174 निर्वाचन-20.01.2023-25 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 21 जनवरी, 2023 ई० (माघ 1, 1944 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

#### सूचना

मेरे पुत्र सचिन कुमार के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश अजीत कुमार दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम अजीत कुमार यादव है। अजीत कुमार यादव पुत्र आदिराम सिंह कृष्ण बलरामनगर, रोहिला मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद।

अजीत कुमार यादव।

#### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भारत एग्रोटेक, पीआर 1, 15 सेकेण्ड फ्लोर नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ-226010, रजि० नं० LUC/0002853 दिनांक 12 मार्च, 2019 में श्रीमती सुधा त्रिपाठी पत्नी उमेश नारायण त्रिपाठी प्रथम व श्रीमती पूजा श्री पत्नी गौरव कुमार सिंह द्वितीय साझेदार थे। दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को द्वितीय साझेदार श्रीमती पूजाश्री फर्म की साझेदारी से हट गयी तथा उनके स्थान पर श्री बाबूराम पुत्र गया लाल, निवासी-ब्लाक सुरसा, थाना सुरसा, ग्राम सुरसा, पोस्ट-सुरसा, जिला हरदोई-241001 को द्वितीय एवं श्री शुभांग पुत्र राम कुमार निवासी-8-टाइप-4, राजभवन कालोनी, राजभवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001 को फर्म की भागीदारी में तृतीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से, पूर्व साझेदार श्रीमती पूजाश्री का भविष्य में उक्त फर्म से कोई लेना देना नहीं रह गया। वर्तमान में

उक्त फर्म में श्रीमती सुधा त्रिपाठी प्रथम, श्री बाबूराम द्वितीय एवं श्री शुभांग तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 से फर्म का पता-पीआर 1, 15 सेकेण्ड फ्लोर नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ-226010 के स्थान पर ग्राम सुरसा, पोस्ट-सुरसा, जिला हरदोई-241001 हो गया।

श्रीमती सुधा त्रिपाठी,  
साझेदार,  
मेसर्स भारत एग्रोटेक,  
पीआर 1, 15 सेकेण्ड फ्लोर नेहरू एन्क्लेव,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010

#### सूचना

मेरे इंटरमीडिएट (CBSE BOARD) के अंकपत्र अनुक्रमांक 5662795 सन् 2015 में माता का नाम RAJVATI CHAUDHARI तथा पिता का नाम RAJESH CHAUDHARI अंकित है जो कि गलत है। हाईस्कूल के अंकपत्र व अन्य विधिक दस्तावेजों में माता का सही नाम RAJVATI और पिता का सही नाम RAJESH KUMAR है।

शुभम चौधरी,  
पुत्र श्री राजेश कुमार,  
निवासी-मकान नम्बर-93, त्रिमूर्ति नगर,  
सरोजनी नगर, लखनऊ।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नारंग सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज, मून्डा खेड़ा रोड, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0 की भागीदार रुबिना बेगम धर्मपत्नी ऐजाज अहमद स्वेच्छा से सदैव के लिये दिनांक 23.11.2022 को अवकाश ग्रहण कर लिया है और हमना खान पुत्री फैयाज अहमद ने नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रही है।

फैयाज अहमद (फर्म भागीदार),  
मेसर्स नारंग सिरेमिक्स इण्डस्ट्रीज,  
मून्डा खेड़ा रोड, खुर्जा-203131,  
जिला बुलन्दशहर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "सागर स्टोन क्रेशर", पता-मौहल्ला तराई, कस्बा शेरकोट, परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01.04.2022 को नजरूल इस्लाम पुत्र असलम, निवासी मौहल्ला नौधना, कस्बा शेरकोट, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर व सत्तार अहमद पुत्र निशार अहमद, निवासी मोहल्ला कोटरा, कस्बा, शेरकोट, तह0 धामपुर, जिला बिजनौर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा दिनांक 01.04.2022 को अनुज कुमार पुत्र हेमेन्द्र सिंह, निवासी मानपुर, शिवपुरी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में दस पार्टनर श्री सरदार खां, श्री आफाक खां, श्री सत्तार खां, श्री सलीम खां, श्री मौ0 शुऐब खां, श्री अफसार खां, श्री कासिम खां, मुनीर खां, श्री जावेद आलम व श्री अनुज कुमार रह गये हैं।

सरदार खां,  
पार्टनर,  
फर्म मेसर्स "सागर स्टोन क्रेशर",  
पता-मौहल्ला तराई, कस्बा शेरकोट,  
परगना व तहसील धामपुर,  
जिला बिजनौर (यू0पी0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम मैना डे पुत्री नृपेन्द्र नाथ सरकार है, जोकि उनके शैक्षणिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। मेरी पत्नी का पुकार का नाम प्रमिला डे है। त्रुटिवश मैंने अपनी सेवा पुस्तिका में पुकार का नाम

प्रमिला डे अंकित करा दिया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी पत्नी का ही हैं, भविष्य में मेरी पत्नी को उनके सही नाम मैना डे पत्नी किशोर कुमार डे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शपथकर्ता,  
किशोर कुमार डे,  
भूतपूर्व मैक-3,  
सर्विस नं0-148685-वाई,  
नि0-एफ-35, साऊथ सिटी,  
रायबरेली रोड, लखनऊ,  
पिनकोड-226025।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम संजीव अग्रवाल पुत्र स्व0 राम चन्द्र अग्रवाल है जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख व मेरी पत्नी के आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5230 0611 6210 में घर का नाम बन्टी अग्रवाल अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही हैं भविष्य में मुझे संजीव अग्रवाल पुत्र स्व0 राम चन्द्र अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

संजीव अग्रवाल,  
पुत्र स्व0 राम चन्द्र अग्रवाल,  
निवासी-1100/2 मीरापुर, नियर कालरा,  
नर्सिंग होम, पोस्ट सिटी, थाना अतरसुईया,  
जनपद प्रयागराज-211003।

### सूचना

फर्म मेसर्स व्यास इंडियन ऑयल मथुरा रोड, राया मथुरा पत्रावली संख्या एजी-15810 में दिनांक 09.07.2020 को प्रथम पक्ष साझेदार श्री राजेन्द्र कुमार व्यास की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती शालिनी व्यास पत्नी स्व0 राजेन्द्र कुमार व्यास, निवासी 1375 जगतपुरी कहारान रूस्तमनगर, सेहसपुर, बिलारी, मुरादाबाद को उनकी हिस्सेदारी देते हुये साझेदारी विलेख दिनांक 09.07.2020 के अनुसार फर्म में सम्मिलित कर लिया गया दिनांक 25.11.2022 को चौधरी सन्दीप सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, निवासी प्लैट नं0 127 करिश्मा अपार्टमेन्ट प्लॉट नं0 27 आईपी एक्सटेंशन पटपड़ गंज, दिल्ली एवं गौरव कुमार पुत्र श्री एदल सिंह, निवासी-नगर पुष्प वाटिका कॉलोनी भरतपुर, राजस्थान को फर्म की भागीदारी में सम्मिलित किया गया तददिनांक को श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल, निवासी-1/78 नियर टी आर एसोसियेट्स भगवती गार्डन एक्सटेंशन, उत्तम

नगर, दिल्ली फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये। वर्तमान फर्म में भागीदारी श्रीमती शालिनी, चौधरी संदीप सिंह, गौरव कुमार है।

श्रीमती शालिनी व्यास,  
साझेदार,  
मेसर्स व्यास इंडियन ऑयल,  
मथुरा रोड राया, मथुरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा एसोसिएट्स 77, अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत, से श्री गुरुवीर सिंह छाबड़ा पुत्र श्री ज्ञान सिंह छाबड़ा, निवासी-मो0 79, अशोक कालोनी, पीलीभीत दिनांक 01.10.2022 से पुर्नगठित होकर, व्यापार प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में (क) श्रीमती बुलबुल छाबड़ा, उम्र लगभग 49 वर्ष पत्नी श्री मानविन्दर सिंह छाबड़ा, निवासी-77, अशोक कालोनी, पीलीभीत और (ख) श्री तेजस्व छाबड़ा, उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र श्री तजेन्द्र सिंह छाबड़ा, निवासी-77, अशोक कालोनी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 01.10.2022 से फर्म का पुर्नगठन करके व्यापार, सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा एसोसिएट्स 77, अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत से प्रारम्भ कर संचालित किया जा रहा है।

श्रीमती बुलबुल छाबड़ा  
(साझीदार फर्म),

सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा एसोसिएट्स 77,  
अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत-262001।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा एसोसिएट्स 77, अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत साझीदारी फर्म के मुख्यालय का नया पता (79, अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत साझीदारी फर्म के मुख्यालय का पुराना पता) में श्रीमती बुलबुल छाबड़ा, पत्नी श्री मानविन्दर सिंह छाबड़ा, निवासी-77, अशोक कालोनी, पीलीभीत तथा श्री तेजस्व छाबड़ा पुत्र श्री तजेन्द्र सिंह छाबड़ा, निवासी-77, अशोक कालोनी, पीलीभीत, दिनांक 23.09.2022 से साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं और फर्म द्वारा दिनांक 23.09.2022 से पुर्नगठित होकर, व्यापार प्रारम्भ कर दिया गया है। साझीदारी फर्म के पूर्व के दो साझीदार (क) श्री गुरुवीर सिंह छाबड़ा उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र श्री ज्ञान सिंह छाबड़ा, निवासी-मो0 79, अशोक कालोनी, पीलीभीत और (ख) श्रीमती सीमा रानी छाबड़ा उम्र लगभग 63 वर्ष पत्नी श्री गुरुवीर सिंह छाबड़ा, निवासी-79, अशोक कालोनी, पीलीभीत, साझीदारी फर्म में यथावत् साझीदार रहेंगे। साझीदारी फर्म सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा

एसोसिएट्स का मुख्यालय, दिनांक 23.09.2022 से 77, अशोक कालोनी, पीलीभीत रखा गया है पूर्व में यह 79 अशोक कालोनी, पीलीभीत था।

श्री गुरुवीर सिंह छाबड़ा,  
साझीदार फर्म,  
जिला सर्वश्री गुरुवीर एण्ड सीमा एसोसिएट्स,  
79 अशोक कालोनी, जिला पीलीभीत-262001।

### सूचना

फर्म मेसर्स देव इण्टरप्राइजेज 10 दि ग्रोस रोड मॉल सिकन्दरा बोदला, आगरा पत्रावली संख्या एजी-14911 में दिनांक 31.03.2017 को श्रीमती दीपा धाकरे पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह चौहान निवासी म0नं0-112, टैगोर नगर दयाल बाग, आगरा फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुई तद्दिनांक को अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 एल0 पी0 गुप्ता, निवासी-127 भरतपुर हाउस, आगरा फर्म की भागीदारी से पृथक् हुये वर्तमान फर्म में भागीदार श्री देवेन्द्र सिंह धाकरे एवं श्रीमती दीपा धाकरे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह धाकरे,  
साझेदार,  
मेसर्स देव इण्टरप्राइजेज,  
10 दि ग्रोस रोड मॉल सिकन्दरा,  
बोदला, आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नारायण मोटर्स, नेशनल हाईवे-24, सिधौली, जिला सीतापुर-261303, रजि0 नं0-/SIT/0003230 का पंजीकरण दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को कराया गया था, जिसमें अवधेश कुमार सिंह प्रथम एवं कौशलेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय साझीदार थे, जिसमें द्वितीय साझीदार दिनांक 07 जनवरी, 2023 से फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर श्रीमती अनुपम उपाध्याय पुत्री श्री विश्वनाथ उपाध्याय, निवासी सी-53, मन्दिर मार्ग रोड, निकट विदिशा पार्क, महानगर एक्सटेशन, लखनऊ-226006, उ0प्र0 को दिनांक 07 जनवरी, 2023 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में अवधेश कुमार सिंह प्रथम एवं श्रीमती अनुपम उपाध्याय द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अवधेश कुमार सिंह,  
साझेदार,  
मेसर्स नारायण मोटर्स।

### सूचना

फर्म मेसर्स जेनेसिस हेल्थ केयर, पता-3/165, विशेष खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के तीन पार्टनर डॉ० सोमनाथ लोंगानी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, डॉ० अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री देवेन्द्र नाथ श्रीवास्तव तथा तृतीय डा० मो० दिलशाद पुत्र मो० जर्जर उ०प्र० साझेदारी से दिनांक 15.12.2022 को हट गये हैं। अब उनके स्थान पर नये पार्टनर श्रीमती ऋचा गंगवार पुत्री मि० सहदेव सिंह गंगवार को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में दो पार्टनर प्रथम पार्टनर श्री कृष्ण प्रताप मल्ल एवं द्वितीय पार्टनर श्रीमती ऋचा गंगवार साझेदार में सम्मिलित हैं।

कृष्ण प्रताप मल्ल,  
पार्टनर,  
निवासी- 3/165, विशेष खण्ड,  
गोमतीनगर, लखनऊ।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रूबी सिंह पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह, निखिल सिंह, आर्यन सिंह व आयुष सिंह पुत्रगण श्री राजीव कुमार सिंह, निवासी एन० 14/49 ए-1, कृष्ण देव नगर, सराय नन्दन, जिला वाराणसी मेसर्स आर० एस० इन्फ्राटेक एन० 14/49 ए-1 कृष्ण देव नगर, सराय नन्दन, जिला वाराणसी, उ०प्र०-221110 के साझेदार रहे हैं। जिसकी पंजीकरण संख्या वी०ए०आर०/0010364 दिनांक 20.10.2021 संख्या 01437/2021/2022 है। फर्म के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना राजकीय राजपत्र में दिनांक 10.12.2022 एवं 07.01.2023 को प्रकाशित करायी गयी थी जिसमें कुछ त्रुटियां थी। संशोधित सूचना यह है कि मूल फर्म का नाम आर० एस० इन्फ्राटेक था। जिसका पंजीकरण दिनांक 20.10.2021 को हुआ था। तत्पश्चात् हम समस्त साझेदारों ने फर्म का नाम परिवर्तित करके दिनांक 30.06.2022 को एस० आर० जी० इन्फ्राटेक कर दिया था। पैन में श्री एस०

आर० जी० इन्फ्राटेक नाम परिवर्तित कराया गया था, किन्तु किन्हीं परिस्थिति वश पंजीकरण का संशोधन नहीं हो पाया। वर्तमान में हम समस्त साझेदारों रूबी सिंह पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह, निखिल सिंह, आर्यन सिंह व आयुष सिंह पुत्रगण श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा फर्म एस० आर० जी० इन्फ्राटेक का नाम दिनांक 01.10.2022 से पुनः परिवर्तित कर दिया गया है। जो मेसर्स एस० जी० आर० इन्फ्राटेक यन 14/49 ए-1 कृष्ण देव नगर, सराय नन्दन, जिला वाराणसी, उ०प्र०-221010 के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

रूबी सिंह।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता श्री दलपत राज जैन जी ने मेरे जन्म के समय मेरे घरेलू नाम लक्ष्मी जैन के नाम से कोलगेट पाल्मोलियम (इण्डिया) के 50-50 शेयर को दो सर्टिफिकेट लिये थे जिसका (1) Folio No. L03996, Certificate No. B7-2058592, Distinctive No. 137758711-137758760 (2) Folio No. CGJ01792, Certificate No. 00518443, Distinctive No. 0042514106-0042514155 है तथा मेरा खाता यूको बैंक हालसी रोड, कानपुर नगर में लक्ष्मी जैन के नाम से चल रहा था जिसका खाता संख्या 01800100001920 है। उसमें भी मैंने लक्ष्मी जैन के नाम को ट्रांसफर कराकर लिंशा जैन करा लिया है जोकि मेरे सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व पैनकार्ड आदि में अंकित है और अब भविष्य में भी मुझे लिंशा जैन पुत्री दलपत राज जैन, निवास 81/84, ई-धनकुट्टी, बम्बईया हाता, कानपुर नगर के नाम से ही जाना जायेगा।

सूचनाकर्त्री,  
लिंशा जैन,  
पुत्री श्री दलपत राज जैन,  
पता-81/84, ई-धनकुट्टी,  
बम्बईया हाता कानपुर नगर।